


तारीख
हुकम

6-6-24

पत्रावली घेश डुर, वकील प्राथिपा उप
विपक्षीगण के सम्मन वाड वागिल से
इए जिले शाण पण किये जाये। विपक्षीगण को
कितनी मतीया कक-कक करे आवाफे डिलापी
के वाड को उपाहित नही, उनके विरुद्ध एव वर
कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जा रहा है
प्राथिपा का प्र-पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी
सम्बन्ध से लिखा जाकर शाण पण किया गया। फा
केसल शुमार होकर नम्बर से कम हो


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



क्रमांक

अंकर-10 श्री हमीर ठाकी निवासी हरिया तहसील माण्डल (हरीया) (संयुक्त खाते)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वारा 111-128 रा.मू.रा.अधि. 1958

दिनांक- 05.08.20

आदेश:-

आर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वारा 111-128 रा.मू.रा.अधि. 1958 का तहत प्रस्तुत हुए निवेदन दिनांक 05.08.2020 पर हरिया माण्डल इलाका हरिया तहसील माण्डल में उदात्त खाते / संयुक्त खाते का संयुक्त खाते कुल किरा 10 रुकवा 3,3259 अक्टोबर महीने में माण्डल न्याय मण्डल के न्याय आचार्यी मुहूर्त दिनांक के सीमा बिन्दु नहीं होने से आठ दिन सीमा सार्वी केवाले इलाका प्रत्येक जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की नूनि की मध्यमगढी का आदेश प्रदान कराया जायें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29-12-23 को मजरीकदु किया जाकर प्रदान की जायें। साथ से यह बात सिद्ध है कि माण्डल नूनि प्रार्थी पत्र तहसील आगत कायल की होने से मध्यमगढी बनाना ही है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों का ध्यान रख कर ही न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार योग्य है।

आदेश:-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वारा 111-128 रा.मू.रा.अधि. 1958 का स्वीकार किया जाकर प्रान्त हरिया तहसील माण्डल में उदात्त खाते / संयुक्त खाते की आगामी 05.08.2020 अक्टोबर माह माण्डल न्याय मण्डल में कुल किरा 10 रुकवा 3,3259 अक्टोबर नूनि का वारा तहसील सीमा की मुहूर्त दिनांक के आधार पर मध्यमगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। मध्यमगढी किये जाने हेतु नू-आमिलख निर्देशक आवनामा 300 रुपये/- कमिश्नर पीस पर कमिश्नर पीस जमा होने पर पक्षमयानु की मौजूदगी में सीमा के खाते को बनाये रखते हुए नुस्तकील बिन्दु का आधार मानकर मध्यमगढी का जायें। फसल नुहई प्रान्त नहीं की जायें।


न्यायालय न्यायालय

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा सविज्ञान कमान पर नियमानुसार मध्यमगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


न्यायालय न्यायालय